अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–11 अंक – 194 | R.N.I.- UPHIN/2012/45127 | लखनऊ रविवार 13 नवम्बर 2022 | पृष्ठ – 4 | मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक उन्नाव एवं क्षेत्राधिकारी सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गैर इरादतन हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल एक अदद डण्डा व अभियुक्त के हाथ में पहना हुआ स्टील का कड़ा बरामद

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। पुलिस अधीक्षकजनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

सीएम योगी ने दिए निर्देश : डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में बनेंगे डेडिकेटेड हॉस्पिटल, घर-घर कराएं स्क्रीनिंग

एक अक्टूबर से प्रारंभ चालू सत्र में अब तक किसानों से 2.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि किसानों की सुविधा के दृष्टिगत सभी क्रय केंद्र क्रियाशील रहें। धान क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर माघमेला की तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में डेंगू व अन्य संचारी रोगों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए रोकथाम के लिए प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिए।

सीएम ने कहा कि विगत कुछ सप्ताह के बीच डेंगू व अन्य संचारी रोगों के दुष्प्रभाव में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनकी बेहतर स्क्रीनिंग के लिए सर्विलांस को बेहतर करने की आवश्यकता है। आशा बहनों का सहयोग लें। घर–घर स्क्रीनिंग कराएं। लक्षणयुक्त मरीजों की पहचान कराते हुए उनके समुचित इलाज की व्यवस्था कराई जाए। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की भांति डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल एक्टिव किये जाएं। कम से कम हर जिले में एक ऐसा डेडिकेटेड अस्पताल जरूर क्रियाशील हो। यहां चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता हो, जांच की सुविधा हो, उपचार की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसे आइसीसीसी से भी जोड़ा जाना चाहिए।

सभी मंत्री फील्ड में बने रहें। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले, उसकी विधिवत चिकित्सकीय जांच हो और समय पर इलाज किया जाए। हमारे सभी मेडिकल कॉलेजों सहित जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी व अन्य उच्च स्तरीय संस्थान साधन संपन्न हैं। इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा अथवा सुरक्षा में तैनात कार्मिकों से मरीजों के तीमारदारों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार बनाने की अपेक्षा है।

स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, पंचायती राज और सूचना विभाग व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। डेंगू के कारण, लक्षण, बचाव आदि के बारे में लोगों को सही जानकारी दी जाए। अखबारों में जागरूकता

परक विज्ञापन, दीवार पेंटिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि के माध्यम से इस बीमारी के कारण प्रभाव और उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। डेंगू मरीजों के लिए हर शासकीय अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्थानीय जरूरतों के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाए। हर जिले में डेंगू टेस्टिंग और प्लेटलेट्स की जांच की सुविधा होनी चाहिए। नगर विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी साफ–सफाई व फॉगिंग का कार्य नियमित कराया जाए। प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर माघमेला की तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। हर श्रद्धालु–हर कल्पवासी अपने व्रत–संकल्प की पूर्ति अपनी आस्था अनुरूप कर सकें, इसके लिए हमें अच्छी व्यवस्था देनी होगी, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। साधु–संतों और कल्पवासियों से संवाद बनाएं। मेला स्थल पर अस्थायी निर्माण का कार्य तेजी से पूर्ण कर लें। प्रयागराज माघ मेला के सुचारु आयोजन के लिए विशेष सचिव और पुलिस अधीक्षक स्तर के एक–एक अधिकारी की तैनाती तत्काल कर दी जाए, मेले की व्यवस्था के प्रति इन अधिकारियों की जवाबदेही होगी। कोविड, डेंगू व अन्य संचारी रोगों से जुड़े एहतियात को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता–सैनिटाइजेशन का कार्य हर दिन जारी रखना होगा। मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएं। प्रयागराज माघ मेले सहित सभी मेलों, पर्वों व त्योहारों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। एक अक्टूबर से प्रारंभ चालू सत्र में अब तक किसानों से 2.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है। किसानों की सुविधा के दृष्टिगत सभी क्रय केंद्र क्रियाशील रहें। धान क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। क्रय केंद्र तक आने वाले हर पात्र किसान से धान खरीद की जाए। भुगतान में कतई विलंब न हो। खाद की कहीं कमी न हो, कालाबाजारी करने वालों के साथ सख्ती से निपटें। अतिवृष्टि के कारण जिन भी जिलों में किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति बिना विलंब कराई जाए। बुन्देलखण्ड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों सहित 50 जिलों के किसान प्रभावित हुए हैं, एक भी प्रभावित किसान क्षतिपूर्ति से वंचित न रहे। युवाओं को निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण का कार्य सुचारु रूप से जारी रखा जाए। हमें अगले पांच वर्षों में दो करोड़ युवाओं को डिजिटल शक्ति से लैस करना है। बिना भेदभाव हर छात्र–छात्रा को टैबलेट/स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाए।

लखनऊ में फिर से बढ़ा वायु प्रदूषण, आईक्यूआई 300 के पार, तालकटोरा और लालबाग में स्थिति सबसे ज्यादा खराब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वायु प्रदूषण बढ़ने से स्थिति और भी खराब होती जा रही है। प्रदूषण के कारण हवा भी जहरीली हो गई है। लोगों को बहुत सी समस्याएं हो रही है। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, दम घुटना आदि कई तरह की परेशानियां हो रही है। इसी समस्याओं को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ जरुरी फैसले भी लिए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सुधार नहीं हो पाया। वही, वायु प्रदूषण से आईक्यूआई भी 300 से पार हो गया है। बता दें कि राजधानी में वायु प्रदूषण से कई इलाकों में हवा बहुत जहरीली हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब स्थिति तालकटोरा और लालबाग इलाके की है। यहां पर आईक्यूआई 300 के पार हो चुका है। जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तालकटोरा, ऐशबाग और नादरगंज इलाके के 35 इंडस्ट्री को नोटिस जारी किया है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उमेश चन्द्र शुक्ला ने तालकटोरा और ऐशबाग क्षेत्र के सभी उद्योगों को बंद करा दिया था। बोर्ड की सख्ती के बाद हालात कुछ बेहतर हो गए थे। चार दिन तक हवा सही रहने के बाद शुक्रवार से प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। वायु प्रदूषण से शुक्रवार को लालबाग क्षेत्र का आईक्यूआइ 325 तक पहुंच गया। यह संख्या अत्यंत खराब श्रेणी में आती है। लालबाग और तालकटोरा के साथ ही अलीगंज क्षेत्र में भी हवा का स्तर खराब स्तर तक पहुंच गया है। हवा का स्तर अत्यंत खराब होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी उमेश चन्द्र शुक्ला की अगुवाई में बोर्ड की टीम ने शहर के निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और कार्रवाई में लगी हुई है। हवा खराब होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक और जिला कृषि अधिकारी को नोटिस जारी किया है। जिला उद्योग को जारी नोटिस में महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वह औद्योगिक क्षेत्र की खराब सड़कों को सुधारे। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में पराली जलाए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला कृषि अधिकारी को नोटिस जारी की गई। इसके साथ ही कुकरैल सहित अन्य वन क्षेत्र में आग जलाने से रोकने के लिए कड़े प्रबंध करने को कहा गया है। वहीं, उन्हें यह भी निर्देश दिए गए है कि अगर कही ऐसी घटनाएं मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

बुखार से एक और मौत, विभाग एलर्ट

अलीगढ़। जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर तहसील के रतनपुर गांव में शुक्रवार रात बुखार से के कारण एक महिला की मौत हो गई है। लोग इसे डेंगू मान रहे हैं और दशहत में हैं। लेकिन एलाइजा टेस्ट न होने के कारण अभी डेंगू की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं बुखार से मौत होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग की टीमें लगातार दौड़ रही हैं और घर–घर जाकर लोगों के सैंपल ले रही हैं। इसके साथ ही इलाके में फॉगिंग की जा रही है और लोगों को जागरुक किया जा रहा है कि वह अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और साफ सफाई रखें। खैर के गांव रतनपुर निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला भूरी देवी पत्नी फूल सिंह पिछले एक सप्ताह से बीमार चल रही थी और बुखार से पीड़ित थी। जिसके बाद शुक्रवार रात उनकी मौत हो गई। इससे एक सप्ताह पहले इसी गांव में इंदवती देवी (50) पत्नी धर्मवीर सिंह की भी मौत हुई थी। गांव में एक सप्ताह के अंदर दो मौते होने के कारण लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव में दो दर्जन से ज्यादा लोग बुखार के कारण पीड़ित हैं और अपने घर में बीमार पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इनके सैंपल लिए हैं और इन्हें दवाइयां व इलाज मुहैय्या कराया जा रहा है। अलीगढ़ में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद सूबे के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक 10 नवंबर को अलीगढ़ आए थे। यहां उन्होंने प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें निर्देश दिए थे कि जिले में लगातार मॉनीटरिंग की जाए। उन्होंने एंबुलेंस में ही डॉक्टर, फार्मासिस्ट और एलटी की नियुक्ति करके घर–घर जाकर सैंपल लेने के निर्देश दिए थे। जिससे कि डेंगू के कहर को रोका जा सके। इसके बाद भी जिले में लगातार मामले सामने आ रहे हैं और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। अलीगढ़ में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 293 हो चुकी है। इसमें 57 मरीज वर्तमान में डेंगू से पीड़ित हैं और उनका इलाज जारी है। वहीं अन्य मरीज ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद लगातार स्वास्थ्य कर्मी, आशाएं और एएनएम शहर और गांव में सर्वे करके बीमार लोगों का पता लगा रही हैं। सीएमओ डॉ नीरज त्यागी ने बताया कि मरने वाली महिला में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई थी। गांव में लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जो गंभीर बीमार हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं अन्य लोगों के घर में ही दवाइयां पहुंचायी जा रही हैं और लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है।

मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने पार्कों का किया निरीक्षण

लखनऊ। लखनऊ की मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने जनेश्वर मिश्र पार्क, डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क, लखनऊ विकास प्राधिकरण (हरिक्षेत्र) यूपी दर्शन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (उपाध्यक्ष) इंद्रमणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। सम्बंधित अधिकारी से कहा कि पार्क के अंदर जो भी केंटीन स्थापित है, उसमें ओवर रेटिंग न हो। फूड जोन के काउंटर, पार्क के बाहर भी लगाया जाए। किड्स–जोन, ओपेन जिम, बैठने की सीट की मरम्मत कराने को कहा हैं। साथ ही पार्क में लगने वाले लेजर शो के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जनेश्वर पार्क में घास कटाई छटाई, कूड़ा उठाना तीन वेंडरो द्वारा कराया जा रहा है। बैठने के बैंच सही कराये जा रहे है। मंडलायुक्त ने डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क में साफ सफाई के कार्य कराने, आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन समय से और बिना किसी कटौती के दिया जाये। वरना संबंधित वेंडर के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

भारतीय सेनाओं में कैरियर के लिए उत्साहित छात्र–छात्राएं, परीक्षा के बताए तरीके

लखनऊ। यूपी गर्ल्स एनसीसी बटालियन (20) द्वारा भारतीय सेनाओं पर भाषण लखनऊ कैंट में आयोजित किया गया। लेक्चर में एनसीसी कैडेटों और आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। यूपीएससी द्वारा लिखित परीक्षाओं, एसएसबी और मेडिकल के बारे में विस्तृत जानकारी कर्नल विनोद जोशी कमान अधिकारी द्वारा दी गई। पांच दिनों तक चलने वाली एसएसबी में विभिन्न टेस्टो के बारे में कमान अधिकारी ने बताया। एसएसबी में चयन तीन कुशल अधिकारियों द्वारा टेस्ट लिए जाते हैं जो व्यक्तित्व, कुशलता और नेतृत्व के गुण पर आधारित होते हैं। 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और टेक्निकल स्नातक द्वारा विभिन्न 17 प्रकार के सेनाओं में कमीशन के बारे में भावी पीढ़ी को विस्तार से बताया गया। कैडेटों और छात्र–छात्राओं ने बहुआयामी प्रश्न भी पूछे। कर्नल विनोद जोशी ने थलसेना, वायुसेना और नौसेना के विभिन्न एडवेंचर खेलकूद, क्रियाकलापों के बारे में बताया, जो राष्ट्र की अंतिम आशा है और अंतिम दम तक सर्वोच्च बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। ताकि राष्ट्र की सभी दिशाओं में सुरक्षा हो सके। कर्नल विनोद जोशी ने बताया कि सेनाओं में सेवा सबसे संतुष्टि का कैरियर है जो विभिन्न सबसे मुश्किल धरातल में सेवा देने का मौका देता है। चाहे ग्लेशियर हो या मरुस्थल या गहरे समुद्र आसमान की ऊंचाइयां। सेनाओं की आगामी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए छात्राओं और छात्रों ने शपथ ली। ताकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक भारत विकास की ओर तीव्र गति से आगे बढ़े।

ईवीएम से होगा नगर निकाय का चुनाव, चुनाव के लिए 2110 कंट्रोल यूनिट और 4405 बैलेट यूनिट की एफएलसी जारी

अलीगढ़। नगर निकाय के चुनाव जैसे–जैसे नजदीक आ रहे हैं, इसकी तैयारियां तेज होती जा रही है। नगर निकाय चुनाव ईवीएम मशीन से ही होंगे। इसके लिए चुनाव अधिकारियों की ओर से मशीनों की एफएलसी (फर्स्ट लेबिल चेकिंग) जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इसकी लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, ईवीएम जोकि पूरे तरीके से तकनीक से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनके तकनीकी पक्षों को समझने में हुई जरा सी लापरवाही सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन के लिए हर तकनीकी पक्ष को मजबूत किया जा रहा है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि अलीगढ़ में नगर निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होंगे। इसलिए नगर निगम निर्वाचन के लिये 2110 कन्ट्रोल यूनिट और 4405 बैलेट यूनिट की एफएलसी की जा रही है। इसकी लगातार सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी हो रही है। उन्होने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए एफएलसी के दौरान होने वाली सारी गतिविधियों की जांच की जा रही है। इसके साथ इसका लाइव प्रसारण भी दिखाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी जब चाहें, इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। कलेक्ट्रेट के वेयर हाउस में यह काम चल रहा है और जल्दी इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। अलीगढ़ में कुल 19 नगर निकाय हैं, जिसमें मतदान किया जाएगा। इसमें 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका परिषद और 16 नगर पंचायतें हैं। नगर पंचायतों में 9 नगर पंचायतें पुरानी हैं, जबकि 7 नगर पंचायतों का सृजन हाल ही में किया गया है। जिसके वोटर बढ़ाने का काम चल रहा है। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम अलीगढ़ और नगर पंचायत इगलास का सीमा विस्तार इस साल ही किया गया है। वहीं नगर पालिका परिषद खैर में 2017 के 28556 मतदाताओं की संख्या बढ़कर 32438 हो गयी है। वहीं नगर पालिका परिषद अतरौली में मतदाताओं की संख्या 46159 हो गयी है।

यूनीव्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी के पार्टनर टेक्नोलॉजी मीट का हुआ उद्घाटन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित होटल जैमिनी कॉन्टिनेंटल में यूनीव्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी के पार्टनर टेक्नोलॉजी मीट का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपमहानिरीक्षक आईपीएस सुभाष चंद्र दुबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत वर्षों में राज्य में जो सुरक्षा का माहौल स्थापित किया है उससे प्रदेश में जनता के बीच बहुत ही सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई है। सुरक्षा टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन नए–नए तकनीक के आने से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इन सुरक्षा और सर्विलांस उपकरणों की मदद से सरकार और प्रशासन उसका पूरा लाभ जनता को पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम संचालक यूनीव्यू के ब्रांच मैनेजर योगेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह मीट हमारे पार्टनर के सुरक्षा एवं सर्विलांस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रोत्साहन को उचित सम्मान देने के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनी का अपने पार्टनरों से संबंध और मजबूत करना और उनको अपने उत्पादों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना है।

कंपनी के इंडिया के निदेशक अश्वनी कुमार ने पार्टनरों द्वारा किए गए कार्यों की खुलकर तारीफ की एवं धन्यवाद प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम प्रतिदिन कंपनी के उत्पादों में आवश्यक सुधार और नई तकनीकी को विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। अश्वनी कुमार ने आगे यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाजार है जहां अपने

उत्पादों की स्थापना करने में हम सबको सहायता मिलेगी। कंपनी के मुख्य इंजीनियर सुभाष ने अपने प्रेजेंटेशन में कंपनी के उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कंपनी के अन्य कर्मचारियों जिसमें सरफराज, रूपा वर्मा ने आगंतुकों की अगवानी की एवं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी।

धनगर के नाम पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाए उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ। आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एस आर दारापुरी द्वारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अलग अलग प्रेषित पत्रों में उक्त मांग उठाई गई है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को संबोधित पत्र में अंकित किया गया है कि 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अंग्रेजी में जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त शासनादेश के सम्बन्ध में पत्र में अंकित किया गया है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूचि के क्रमांक 27 पर अंकित जाति का नाम अंग्रेजी में (DHANGAR) और हिंदी में "धन्गड़" अंकित है जोकि अधिकतर सोनभद्र जिले में रहती है. इसका यह अभिप्राय है कि यह जाति धन्गड़ है न कि धनगर जैसाकि अंग्रेजी के हिज्जों से लगता है. यह ज्ञात हुआ है पच्छिमी उत्तर की पाल,गडरिया (पिछड़ी) जाति के कुछ लोग जो अपने आप को धनगर गोत्र का होने का दावा करते हैं, भी वींदहंत के नाम से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करा रहे हैं। श्री दारापुरी ने आगे कहा है कि इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए परंतु पाल,गडरिया की धनगर गोत्र वाली उपजाति के कुछ लोग अभी भी गलत ढंग से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं जिस पर तुरंत रोक लगाई जाए। अतः शासन को प्रेषित पत्र में अनुरोध किया गया है कि वर्तमान शासनादेश के अनुपालन में अंग्रेजी में वींदहंत जाति के नाम से जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि यह केवल सोनभद्र में रहने वाली धन्गड़ जाति को ही देय है न कि पालध्गडरिया (पिछड़ी जाति) की धनगर गोत्र वाली उपजाति को। पत्र में इस सम्बन्ध में उच्च प्राथमिकता पर कार्रवाही करने का अनुरोध किया गया है ताकि वर्तमान शासनादेश का लाभ अपात्र लोग न उठा सकें और धन्गड़ जाति के लोगों के अधिकारों का और अधिक हनन न हो जोकि पहले ही सरकार की गलत एवं अवैधानिक नीतियों के कारण हो चुका है। उपरोक्त के इलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित एक अन्य पत्र में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूचि के क्रमांक 27 पर अंग्रेजी में 'वींदहंत' और हिंदी में 'धन्गड़' अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में आगे अंकित किया गया है कि इस क्रमांक पर हिंदी में अंकित 'धन्गड़' नाम गलत है जबकि इस जाति का सही नाम धांगर है जोकि अधिकतर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रहती है. इस बात की पुष्टि 2001 की Series–1, Primary Census Abstract Scheduled Castes: Tables A–8 के पृष्ठ संख्या 382 की प्रतिलिपि पर उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूचि के क्रमांक 27 पर प्रविष्टी से भी की जा सकती है। इस तथा 2011 की जनगणना में इस जाति की जनगणना 'धांगर' के नाम से ही की गयी थी न कि 'धन्गड़' के नाम से। दारापुरी द्वारा प्रेषित पत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग एवं भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूचि के क्रमांक 27 पर अंग्रेजी में 'वींदहंत' और हिंदी में 'धन्गड़' अंकित नाम को संशोधित कराकर हिंदी में 'धांगर' अंकित कराने की व्यवस्था करें ताकि धाँगर जाति के लोगों को सही नाम से जाति प्रमाण पत्र मिल सकें।

सम्पादकीय

जीएम फसलों पर दूरगामी नीति बने

बीस वर्षों तक चले वाद–विवाद और विरोधों के बीच पहली जीएम फसल सरसों की व्यावसायिक खेती की मंजूरी दे दी गयी है। बायोटेक नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के इस निर्णय का विरोध कई हरित समूहों एवं किसान संगठनों द्वारा हो रहा है. सबसे मुखर स्वर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ एवं स्वदेशी जागरण मंच का है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी आंदोलन की धमकी दी है, पर सबसे चकित करने वाला बयान सीपीएम के किसान संगठन से आया कि वे इस तकनीक की सराहना करते हैं। स्वदेशी जागरण मंच का आरोप है कि जीईएसी गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रही है तथा जीएम सरसों के समर्थन में किये जा रहे दावे पूरी तरह गलत हैं. जीईएसी ने एक अनुमति पत्र में कहा है कि समर्थन में प्राप्त सभी जानकारी विदेश से लायी गयी थी। हमारे देश में अध्ययन होना बाकी है। इन संगठनों का आरोप है कि यदि भारत में

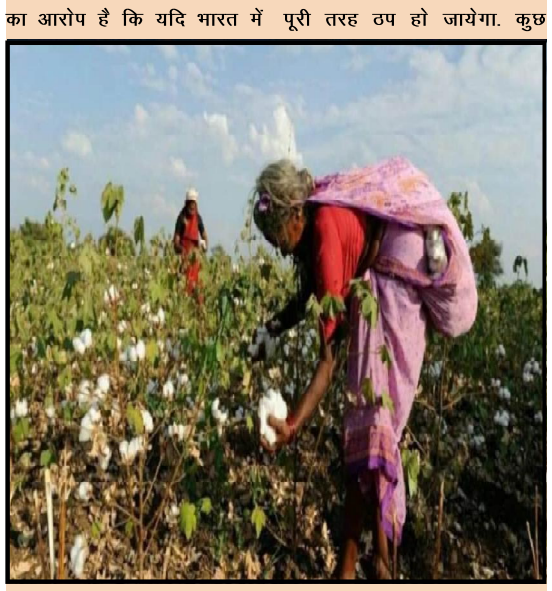

कोई अध्ययन नहीं किया गया, तो जीईएसी गैर जिम्मेदार और अवैधानिक निर्णय कैसे ले सकती है. इससे पूर्व जीएम बीटी कॉटन को लेकर भी भ्रामक प्रचार किये गये थे कि इसको कीड़ों से कोई नुकसान नहीं होगा और उत्पादन ज्यादा होगा, मगर पिछले 17 वर्षों से बीटी कपास के उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है. फिर भी किसानों को सपने दिखाये जा रहे हैं। कृषि मामलों की संसदीय समिति ने अपनी 37वीं रिपोर्ट में बताया है कि बीटी कॉटन की व्यावसायिक खेती करने में कपास उत्पादकों की माली हालत बजाय सुधरने के बिगड़ गयी. इसमें कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना पड़ा. महाराष्ट्र में पिछले दिनों कपास को कीड़े से बचाने की जुगत में किसानों द्वारा अनजाने में मौत को गले लगाने के मामले प्रकाश में आये हैं। इन मौतों की वजह वह कीटनाशक बताया गया है, जिसे उन्होंने फसलों पर कीड़े खत्म करने के लिए छिड़का था। जीएम फसलों की खेती केवल छह देशों– अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत और अर्जेंटीना– में हो रही है। दुनिया में कुछ 18 करोड़ हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है. वर्ष 1951–52 के दौरान देश में मात्र 52 मिलियन टन अनाज का उत्पादन होता था, लेकिन आज बिना जीएम तकनीक के 300 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन हुआ है. पहले हम गेहूं, चावल, शक्कर के लिए विदेशी आयात पर निर्भर करते रहे हैं, पर आज हम इनके बड़े निर्यातक हैं। पिछले दो वर्षों से 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त पांच किलो राशन उपलब्ध कराना हमारी कृषि सफलता का प्रमाण है। अधिकतर संगठनों एवं विशेषज्ञों का कहना है कि कमेटी का निर्णय दबाव और जल्दबाजी में लिया गया है और जिस वेरायटी को मंजूरी दी गयी है, वह कम पैदावार वाली है एवं इससे उत्पादित तेल की गुणवत्ता भी कम है। भारतीय सरसों का तीखापन उसका सबसे बड़ा गुण है, जो नयी किस्म से नदारद है। वर्तमान में जीएम सरसों की श्रेणी डीएमएच–11 से भी ज्यादा उपज की चार वेरायटी भारत में पहले से ही मौजूद हैं. कॉन्फेडरेशन ऑफ एपीकल्चर के अनुसार जीएम तरीके से सरसों की खेती की शुरुआत होने पर शहद की खेती के बर्बाद होने की संभावना है। इससे 10 लाख मधुमक्खी पालकों के जीवनयापन पर संकट आ जायेगा. स्मरण रहे, मधुमक्खियों के परागण में सरसों की खेती का अहम योगदान होता है. ज्यादातर जगहों पर चिकित्सकीय गुणों की वजह जीएम मुक्त सरसों के शहद की मांग है। ऐसे में शहद निर्यात पूरी तरह ठप हो जायेगा. कुछ बड़ी कंपनियों का मकसद है दूसरी किस्म का जीएम क्रॉप मॉडिफाई बनाना. जिस फसल पर भी इसका प्रयोग होगा, वहां उस फसल के अलावा सब खत्म हो जायेगा. घातक रसायनों से फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. भूमि की उर्वरता भी खत्म होती है। सरकार एक तरफ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करती है, दूसरी तरफ ऐसी नीतियां लाकर रसायनों के प्रभाव को बढ़ाती है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जीएम फसलों के प्रयोग से पहले भूमि परीक्षण अनिवार्य बनाने की सिफारिश कर चुके हैं। अमेरिका के मात्र एक फीसदी भू–भाग में जीएम मक्के की खेती की गयी थी, जिसने 50 फीसदी गैर जीएम खेती को संक्रमित कर दिया। चीन में भी किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2014 के बाद वहां जीएम खेती नहीं हो रही है। अमेरिकी कंपनी मोनसेंटो देश में इस व्यावसायिक खेती की बड़ी पैरोकार है. साल 2011 में अमेरिका में भी इसी कंपनी ने सूखा प्रतिरोधी जीएम मक्का जारी किया था, पर थोड़े ही समय में अमेरिकी कृषि विभाग ने स्वीकार किया कि यह गैर जीएम किस्मों से ज्यादा प्रभावी नहीं है। भारत में मोनसेंटो ने 1970 से खर–पतवार नाशक रसायनों के उत्पादन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करायी थी। लगभग दस वर्ष पूर्व बीटी कपास यही कंपनी लायी. नीति–निर्धारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका कोई भी प्रस्ताव किसानों और उपभोक्ताओं के हित में हो। ऐसे फैसले लेने से पहले देश में आम सहमति भी बनानी चाहिए।

आधुनिक शिक्षा के वास्तुकार थे मौलाना आजाद

इबरार अहमद

भारतीय समाज को सजाने–संवारने में जिन महापुरुषों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनमें एक नाम मौलाना आजाद का भी है। वे एक सहाफी, सियासतदां, जंग–ए–आजादी के मुजाहिद तो थे ही, महान शिक्षाविद भी थे. इन्हें आजाद हिंदुस्तान में आधुनिक शिक्षा का आर्किटेक्ट कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजाद भारत किस तरह प्रगति के रास्ते पर चलेगा, इसका एक सपना गांधी जी ने घरेलू उद्योग का स्वरूप लिये आत्मनिर्भर गांव के रूप में देखा था, जो शक्तिशाली भारत का आधार होगा. दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू एवं उनके साथियों की सोच थी कि भारत आधुनिक बड़े उद्योग और आर्थिक सक्रियता का बड़ा केंद्र बने, ताकि विकसित देशों के साथ खड़ा हो सके। मौलाना आजाद ने इन दोनों विचारों के बीच सामंजस्य बनाते हुए एक ऐसी शिक्षा नीति पेश की, जिसमें प्राचीन शिक्षा और सभ्यता का समावेश भी है. गांव की मिट्टी की सुगंध, संस्कृति और सभ्यता का अद्भुत मिश्रण है।

अबुल कलाम आजाद की शख्सियत एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक युग की थी। वे कहते हैं– 'हम अपने भौतिक धन और साज–ओ–सामान को भौगोलिक सीमाओं में कैद कर सकते हैं, लेकिन इल्म व तहजीब की दौलत पर पाबंदी नहीं लगा सकते. वह तो इंसान की मीरास है।' मौलाना के जेहन में यह बात साफ थी कि शिक्षा केवल कारोबारी या आर्थिक समस्या नहीं है. मौलाना के नजदीक तालीम का उद्देश्य था कि इंसान के व्यक्तित्व में चमक पैदा हो. हमेशा पुनर्निर्माण की तरफ अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्र रूप से सरंचना कर अपनी पहचान बनायी जाए. जब देश आजाद हुआ, तो मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री बने। उस समय महात्मा गांधी जीवित थे और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी का अपना शैक्षणिक दृष्टिकोण था। वे देश को मशीनों के हाथों में देने पर सहमत नहीं थे और न उसे मशीनों की हुकूमत की तरफ ले जाना चाहते थे। वे बड़े उद्योगों की तुलना में गांव की तरक्की और घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करने के पक्ष में थे। नेहरू बड़े उद्योगों की स्थापना के हक में थे. ऐसी स्थिति में प्रश्न यह था कि देशवासियों को किस तरह की शिक्षा दी जाए? मौलाना ने बीच का रास्ता निकाला. उन्होंने तय किया कि हमारे विद्यार्थी ऐसे निकलें, जो बड़े उद्योग चला सकें और साइंस व टेक्नोलॉजी के नये–नये आविष्कार पर काबू पा सकें, साथ ही घरेलू उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिल सके. अपनी इस योजना को साकार करने के लिए मौलाना आजाद ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर के नेतृत्व में विज्ञान के उच्च शोध संस्थान की स्थापना की. एटमी तरक्की का एक अलग संस्थान स्थापित किया गया. इसके अलावा विज्ञान, कृषि, चिकित्सा आदि में शोध एवं अनुसंधान के शीर्ष संस्थानों की स्थापना की गयी।

उद्देश्य था कि कृषि एवं उद्योग दोनों को प्रोत्साहन मिल सके. मौलाना आजाद ने आजाद हिंदुस्तान में उच्च शिक्षा की प्रगति एवं प्रसार पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया। उन्होंने 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की और डॉक्टर राधाकृष्णन को इसका अध्यक्ष बनाया. माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया।

उन्होंने महसूस कर लिया था कि देश उस वक्त तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और प्रगति की राह पर नहीं चल सकता, जब तक साइंस एवं टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जायेगा. इसके लिए 1951 में खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी की स्थापना की गयी। मौलाना आजाद ने 18 अगस्त 1951 को इस संस्था की बुनियाद रखते हुए कहा था– 'मेरा पहला काम था कि टेक्निकल तालीम की तरफ ध्यान दूं ताकि इस सिलसिले में हम आत्मनिर्भर हो सकें.हमारे बहुत से नौजवान, जो इस तालीम की प्राप्ति के लिए विदेश जाते हैं, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, जब विदेशों के विद्यार्थी हिंदुस्तान में इस तालीम को हासिल करने आयें।' उनका ध्यान समाज विज्ञान और ललित कला की तरफ भी विशेष रूप से रहा. उन्होंने इतिहास अनुसंधान तथा समाज विज्ञान अनुसंधान परिषदों को स्थापित किया. उनके द्वारा स्थापित एक और संस्थान– अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान– ने बाद में प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया. मौलाना आजाद की शिक्षा दृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।

फीस की टीस

लोक कल्याणकारी शासन की जवाबदेही से भागती सरकारों और शिक्षण संस्थाओं के व्यापार के केंद्र बनने की जिस चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यक्त किया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि प्रतिभाओं को मोटी फीस की टीस न चुभे। विडंबना यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनेताओं की गहरी होती दखल से यह रोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कारोबार का यह रोग अब मेडिकल पढ़ाई के उस क्षेत्र में भी फैलने लगा है जहां धरती पर दूसरे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर तैयार होते हैं। जब ये प्रतिभावान बच्चे परिवार का पेट काटकर जमा पैसे से पढ़ाई करेंगे तो क्या समाज में सस्ती चिकित्सा गरीबों को मिल सकेगी? या फिर वे महंगी शिक्षा पूरी करने के बाद खर्च किये रुपयों की उगाही में लग जाएंगे? संकट यह भी है कि मोटा पैसा खर्च कर सकने वाले अयोग्य लोग डिग्री हासिल कर सकेंगे और पैसा न जुटा सकने वाली प्रतिभाएं हमें डॉक्टर के रूप में नहीं मिल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश के मेडिकल कालेजों में ट्यूशन फीस सात गुना बढ़ाकर 24 लाख सालाना करने के निर्णय पर रोक लगाने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को यथावत् रखने के बाद की गई। कोर्ट ने इस बढ़ोतरी को अनुचित और फीस निर्धारण करने वाले नियमों का उल्लंघन बताया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में बिना उचित मंजूरी के कई ऐसे बुनियादी ढांचे खड़े किये गये हैं, जो खुलेआम मुनाफाखोरी के मकसद से व्यवसाय कर रहे हैं। ये संस्थान पेड सीट्स और कैपिटेशन फीस लेकर फल–फूल रहे हैं। जिसमें योग्यता को दरकिनार कर दिया जाता है। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों के मेधावी बच्चों का कठिन तैयारी के बावजूद डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाना असंभव होता जा रहा है। नीति–नियंताओं का दिवालियापन देखिये कि देश में योग्य चिकित्सकों की भारी कमी के बावजूद प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। यह दुखद है कि इन शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की मनमानी रोकने में केंद्रीय नियामक संस्थाएं बेदम नजर आ रही हैं। जिसके चलते चिकित्सा शिक्षा के ढांचे में जरूरी सुधार नहीं हो पा रहे हैं। जबकि देश में पारदर्शी, गुणात्मक व जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत है। निस्संदेह कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता और आंध्र सरकार पर पांच लाख का जुर्माना वक्त की जरूरत है क्योंकि देश में विशेषज्ञता वाला शिक्षण बहुत महंगा हो गया है। जिसके चलते सस्ती व उम्दा पढ़ाई के लिये भारतीय प्रतिभा का विदेशों में पलायन हो रहा है। हाल में यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की दुर्दशा जगजाहिर है। वहीं दूसरी ओर, हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ मेडिकल के छात्र आंदोलनरत हैं। पीजीआई रोहतक में एमबीबीएस के छात्रों के लिये सरकार ने करीब दस लाख रुपये का बॉन्ड भरने की शर्त रखी है, जिसके खिलाफ छात्र–छात्राएं सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। सोचा जा सकता है कि इन हालात में ईमानदारी से नौकरी कर रहा व्यक्ति कभी अपने बच्चों को डॉक्टर कैसे बना पायेगा। निस्संदेह, यह खर्चा अभिभावकों की कमर तोड़ने वाला है। महंगाई के इस दौर में कोई कैसे इतना पैसा अपने एक बच्चे पर खर्च कर पायेगा। निस्संदेह यह सत्ताधीशों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही है। बहुत संभव है कि यह राशि न जमा कर पाने के कारण कई प्रतिभाएं आगे पढ़ने से वंचित रह जायें। पास के उत्तर प्रदेश व एम्स में यह फीस मात्र हजारों में है। ऐसे में प्रतिभाओं का पलायन स्वाभाविक ही है। कठिन परिश्रम से मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के साथ यह अन्याय ही है। निश्चित रूप से यह समाज का नुकसान भी है क्योंकि उन्हें योग्य चिकित्सक के बजाय मोटी रकम देकर पढ़ने वाले डॉक्टर ही मिलेंगे। निस्संदेह, इतना पैसा देकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के दिमाग पर डॉक्टर बनने के बाद भी कर्ज का मर्ज चढ़ा रहेगा।

10 लाख नौकरी, बदला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम, गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र किया जारी

गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तमाम दल चुनावी मोड में नजर आ रही है। जहां एक तरफ दल चुनावी जनसभाओं, रैलियों और रोड शो में

बड़े–बड़े वादों के पिटारे खोल मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं घोषणापत्र के जरिये भी तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में हर गुजराती के लिए 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई के साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बकाया बिजली बिल माफ करने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल स्टेडियम करने का वादा किया है। पार्टी की ओर से ये भी कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पहली कैबिनेट मीटिंग से ही इसे सरकार का आधिकारिक दस्तावेज बनाकर काम किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि हमने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस गुजरात में कूदेगी वह (आप) नज़र नहीं आएंगे, आज वह नज़र नहीं आ रहे। मैं हिमाचल से आया हूं। ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने वहां से अपना पूरा प्रचार वापस ले लिया? उन्होंने अपने उम्मीदवार वापस नहीं लिए। आप बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। मोरबी कांड को गंभीरता से समझें। उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अधीन आयोग गठित करने में सरकार को क्या समस्या है? यदि लोगों को दंडित किया जाता है, तो लोग भविष्य में सावधान रहेंगे। यानी शासन–प्रशासन यहां जीरो है।

पर्यावरण एवं उद्योग

देशों और शहरों की तरह दुनियाभर में बड़ी औद्योगिक एवं कारोबारी कंपनियों ने अपने स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने का संकल्प लिया है. लेकिन वास्तविकता यह है कि इन संकल्पों को लेकर उनकी समुचित प्रतिबद्धता नहीं हैं। मिस्र के शर्म अल–शेख में चल रहे जलवायु सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कंपनियों के व्यवहार की विसंगतियों को रेखांकित किया है. उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो कंपनियां उत्सर्जन घटाने और निर्धारित समय के भीतर उसे शून्य के स्तर पर लाने की बातें करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे जीवाश्म ईंधनों में निवेश करती हैं, अपनी गतिविधियों से वनों का क्षरण करती हैं तथा उत्सर्जन घटाने के बजाय बढ़ाती हैं। जैसा कि गुटेरेस ने कहा है कि उत्सर्जन कम करने के झूठे वादे निंदनीय हैं। इस तरह की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित बिंदुओं के अनुसार शहरों और क्षेत्रों को अपने संकल्पों की समीक्षा कर एक साल के भीतर रिपोर्ट देनी चाहिए. यह स्वागतयोग्य है कि अनेक देशों और क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है तथा उसके परिणाम भी संतोषजनक हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में सौर ऊर्जा पैनलों को लगाने का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में भी लोगों की दिलचस्पी में बढ़ोतरी हो रही है. लेकिन एक देश या कुछ क्षेत्र की ऐसे उपलब्धियों से ही जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने की गंभीर चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है। उत्सर्जन कम करने के प्रयास हर स्तर पर होना चाहिए. इसमें शहरों और उद्योगों की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए क्योंकि तापमान बढ़ने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार यही हैं। स्थिति यह है कि एक ओर उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी नहीं आ रही है, पर दूसरी ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से ने इसे घटाने का कोई–न–कोई संकल्प लिया हुआ है। आगामी दशकों में अगर उत्सर्जन के स्तर को शून्य तक लाना है, तो उत्सर्जन में लगातार बड़ी कमी करनी होगी तथा स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ाना होगा. एक बड़ी समस्या यह है कि कंपनियां इस दिशा में क्या कर रही हैं, उसका आकलन कर पाना बहुत कठिन है. इसके लिए पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है. कंपनियों के कहे पर भरोसा करना दुनिया के लिए आत्मघाती होगा. पेरिस समझौते में यह निर्णय लिया गया था कि पूर्व औद्योगिक स्तर से तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इसके लिए 2030 तक उत्सर्जन को आधा करना होगा। आशा है कि उद्योग जगत अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभायेगा।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव परिणाम ने डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है

अमेरिका में मध्यावधि चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी की एकतरफा लहर की जो संभावना जताई जा रही थी वह गलत साबित हुई है। पूर्वानुमानों के विपरीत जो बाइडन कई दशकों के अमेरिकी इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति बन गये हैं जिनके नेतृत्व वाली पार्टी ने मध्यावधि चुनावों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रदर्शन से खुश जो बाइडन अपने अगले कार्यकाल को लेकर भी बहुत आशान्वित नजर आ रहे हैं लेकिन देखना होगा कि उम्र उनका साथ देती है या नहीं। चुनावों के अब तक सामने आये परिणाम यह भी दर्शा रहे हैं कि अमेरिकी जनता ने बीच का रास्ता अपनाया है और किसी एक पार्टी को वह प्रचंड बहुमत देने से बची है।

इन चुनावों से अमेरिकी राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव पर गौर करें तो एक बात पहले ही स्पष्ट है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव अपने आप में काफी मायने रखते हैं क्योंकि यह 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी भी है। इसीलिए डेमोक्रेट्स ने मध्यावधि चुनाव को न केवल बाइडन प्रशासन की नीतियों पर वोट के रूप में, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र के भविष्य पर एक जनमत संग्रह के रूप में भी तैयार करते हुए चुनाव लड़ा। बाइडन ने इन चुनाव परिणाम से अपनी स्थिति मजबूत की है तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ट्रंप पहले ही कई तरह की जांचों का सामना कर रहे हैं और अब जनता ने भी उनका पूरी तरह साथ नहीं दिया है।

इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के एकछत्र नेता के रूप में अब तक ट्रंप बने हुए थे लेकिन अब पार्टी पर ट्रंप की पकड़ को उनके प्रतिद्वंद्वी रॉन डेसेंटिस चुनौती दे सकते हैं जिन्होंने फ्लोरिडा के गवर्नर की दौड़ में दोहरे अंकों के अंतर से जीत हासिल की है। डेसेंटिस रिपब्लिकन की पहली पसंद बनते जा रहे हैं और संभव है कि वह 2024 के राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में भी शामिल हो जायें। डेसेंटिस के उभार से ट्रंप भी भड़के हुए हैं। उनके हालिया बयानों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि डेमोक्रेट्स से ज्यादा गुस्सा उन्होंने डेसेंटिस पर उतारा है। इन चुनावों के अब तक आये परिणामों पर नजर डाली जाये तो कहा जा सकता है कि ट्रंप का आशीर्वाद जीत की निश्चित गारंटी नहीं था। उम्मीदवार की गुणवत्ता अमेरिका में अभी भी मायने रखती है।

दूसरी ओर, भारतीय–अमेरिकी उम्मीदवारों की जीत इस छोटे जातीय समुदाय की तेजी से बढ़ती महत्वाकांक्षा को साफ प्रदर्शित कर रही है। हालांकि अमेरिका में भारतीय–अमेरिकी समुदाय की आबादी को देखें तो यह अमेरिका की करीब 33.19 करोड़ की आबादी का सिर्फ एक प्रतिशत है। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में जीत दर्ज कर सत्तारुढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के पांच भारतीय–अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल और एमी बेरा ने जहां अमेरिकी की प्रतिनिधि सभा में अपनी जगह पक्की कर ली है तो वहीं कई भारतीय–अमेरिकियों ने राज्य विधायिका चुनाव में जीत दर्ज कर आगे के राजनीतिक रास्ते खोल लिये हैं। भारतीय–अमेरिकी उद्यमी एवं राजनेता श्री थानेदार मिशिगन से कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय–अमेरिकी बन गये हैं तो इलिनॉयस के आठवें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में राजा कृष्णमूर्ति ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की। कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में भारतीय–अमेरिकी रो खन्ना जीते हैं तो दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इकलौती भारतीय–अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने रिपब्लिकन के क्लिफ मून को वाशिंगटन के सातवें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में मात दे दी है। कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले एमी बेरा ने कैलिफोर्निया के सातवें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में जीत हासिल की है। राज्य विधायिकाओं में मेरीलैंड में अरुणा मिलर ने जीत दर्ज की और लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर काबिज होने वाली पहली भारतीय–अमेरिकी राजनेता बनीं हैं। इसके अलावा भी कई युवा भारतीयों ने विभिन्न क्षेत्रों में जीत हासिल की है।

<u>चुनाव परिणाम का भारत पर क्या होगा असर?</u>

मध्यावधि चुनाव परिणाम के भारत और अमेरिका के संबंध पर असर की बात करें तो कहा जा सकता है कि इन परिणामों का दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अगले साल इन्हें और गति ही मिल सकती है। देखा जाये तो भारत और अमेरिका के दिपक्षीय संबंधों को अमेरिका के दोनों दलों का समर्थन मिलता रहा है। क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को लेकर चिंता जैसे साझा हित के मुद्दे दोनों देशों को जोड़ते हैं। इसके अलावा यह भी सर्वविदित है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी इस बात को लेकर एक राय रखती हैं कि भारत के साथ सुरक्षा और वाणिज्यिक संबंध पहली प्राथमिकता है। खासकर हिंद–प्रशांत में चीन को रोकने के लिए भारत के साथ तालमेल जरूरी है। इसके अलावा वाणिज्यिक, रक्षा और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए क्वाड, आई2यू2 और आईपीईएफ में भी दोनों देशों के बीच तालमेल कायम किया गया है।

<u>अमेरिका में क्या बदलेगा?</u>

बहरहाल, जहां तक मध्यावधि चुनाव परिणाम के बाद अमेरिका में घरेलू नीतियों में आने वाले संभावित बदलाव की बात करें तो हो सकता है कि अब सरकारी खर्च में कटौती हो। क्योंकि सरकारी खर्च बाइडेन प्रशासन के तहत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इसके अलावा रिपब्लिकन नेतृत्व अमेरिकी ट्रेजरी के लिए ऋण सीमा में वृद्धि की अनुमति देने के बदले में सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर में सुधार के लिए डेमोक्रेट्स को मजबूर करने की कोशिश कर सकता है। चुनाव परिणाम चूंकि बाइडन प्रशासन की नीतियों पर जनता की मुहर है इसलिए बाइडन अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के साथ ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आने वाले दिनों में कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। फिलहाल तो सभी नजरें जी–20 से इतर बाइडन और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात पर लग गयी हैं।

–गौतम मोरारका

कलेक्टर ने किया खाद गोदाम कचनी का औचक निरीक्षण

खाद वितरण केन्द्र पर कलेक्टर ने किसानो से की चर्चा

जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। सिंगरौली कलेक्टर अरूण कुमार परमार के द्वारा आज खाद गोदाम कचनी का औचक निरीक्षण कर किसानो से चर्चा की गई उन्होने मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिये कि किसानो को उनकी जरूरता के

व्यवस्थाओ का जायजा लिया गया। कलेक्टर के द्वारा गोदाम मे खाद भण्डारण की व्यवस्था किसानो को खाद उपलंब्ध कराने की प्रक्रिया आदि का निरीक्षण कर उपस्थित हिसाब के खाद उपलंब्ध कराये इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी आशीष पाण्डेय, उपायुक्त सहकारिता आर.एस. गुप्ता, गोदाम प्रभारी महेन्द्र पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

एनटीपीसी दृविंध्याचल सीएसआर द्वारा पैरामिलिट्री,राज्य पुलिस एवं आर्मी डिफेंस प्रशिक्षण हेतु युवक एवं युवतियो के चयन हेतु शिविर का आयोजन

अवध की आवाज ब्यूरो

मध्य प्रदेश। जिला सिंगरौली एनटीपीसी,विंध्याचल द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों मे नैगम सामाजिक दायित्व नीति के तहत विकास से संबन्धित विभिन्न कार्य कराये जाते है इसी क्रम मे एनटीपीसी –विंध्याचल सीएसआर द्वारा जिले के 50 युवक एवं युवतियों को 3 माह के पैरामिलिट्री, राज्य पुलिस एवं आर्मी डिफेंस की तैयारी के लिए उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश सेड़मैप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। चयन के लिए शारीरिक जांच हेतु 2 दिवसीय शिविर का आयोजन दिनांक–11.11.2022 एवं 12.11. 20222 को किया जा रहा है प्रथम दिवस कुल –127 युवक एवं युवतियां चयन प्रक्रिया मे उपस्थित हुये कुल –66 युवक एवं 29 युवतियां शारीरिक जांच सम्मलित हुये जांच शिविर के दौरान उदघाटन के दौरान अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन स्नेहाशीष भट्टाचार्या, उप महाप्रबंधक मानव संसाधन दृ

सीएसआर एंड आर–आर श्री कन्हैयालाल, सीएसआर टीम के सदस्य एवं उद्यमिता विकास केंद्र सेड़मैप से श्री अशोक त्रिपाठी अपने टीम के साथ उपस्थित रहे। उक्त ट्रेनिंग के अतिरिक्त सैनेटरि पैड निर्माण,बेसिक कम्प्युटर आपरेटर प्रशिक्षण,मशरूम उत्पादन,टेराकोटा प्रशिक्षण,सहद उत्पादन,डेयरी उत्पाद निर्माण, आचार एवं पापड़ निर्माण ,मुर्गी पालन पॉल्ट्री फार्म प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

13 वा उर्से पाक शाहजी रफीकुल औलिया का आगाज

अवध की आवाज ब्यूरो

बरेली। बरेली में खानकाहे शाहजी रफीकुल औलिया के सज्जादा नशीन हजरत मुहीब मियां रफीकी कदीरी साहब की सरपरस्ती में उर्स किया जा रहा है। खानकाहे शाहजी रफीकुल औलिया के मीडिया प्रभारी डॉ सैयद सरताज हुसैन अब्बासी ने बताया कि चांद से 13 वा शाह जी रफीकुल औलिया जिसकी पहली तारीख बाद नमाज ईशा बरोज हफ़्ता तारीख 12 नवंबर 2022 मुताबिक 16 वरिउससानी 1441 हिजरी को जश्ने गौसुल वरा बरोज इतवार कुल शरीफ हजरत शाहजी रफीकुल औलिया जिसका 9:00 बज कर 40 मिनट में कुल की रस्म अदा होगी जिसमें जश्ने गौसुल वरा में आने वाले मुकर्रर व नातखा का हजरात ख़तीब अल्लामा मुफ्ती अतीक अहमद साहब कदीरी दरबारे अल्लाहु मियां पीलीभीत शरीफ बुलबुले बागे मदीना हजरत मौलाना शराफत हुसैन कदरी दरवाजे अल्लाहु मियां पीलीभीत शरीफ खतीब इमाम हाफिज सलीम साहब कदरी खानकाहे शाहजी रफीकुल औलिया बरेली शरीफ हजरत कारी यासीन कदरी खतीब इमाम सुनहरी मस्जिद बरेली शरीफ कुल शरीफ में मेहमान हजरत साहबान मियां शेरी साहब बहेडी शरीफ रहेंगे प्रोग्राम के निजामत जनाब मुस्तकीम कादरी पीलीभीत शरीफ के सुपुर्द रहेगी।

भारी मात्रा मे नकली डी ए पी खाद बरामद

अवध की आवाज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। मनीष गुप्ता नाम के कारोबारी के यहाँ पड़ा छापा, भारी मात्रा में नकली डीएपी खाद बरामद.....हजारों बोरी नकली खाद बरामद

नेपाल तक जाती थी इस कारखाने से बनी खाद

फर्म का नाम गोविंद इंडस्ट्रीज

प्रशासन की नाक के नीचे कई सालों से फल फूल रहा था नकली खाद का अवैध कारोबार

उद्योग महाप्रबंधक का बगल में ही है आफिस

हर साल चेकिंग के बाद जारी होता है रिनीवल प्रमाणपत्र

राजापुर चौकी मुश्किल से 100 मीटर दूर।

लखीमपुर खीरी मुद्रा लोन के नाम पर चार करोड़ की रकम डकार गए बिचौलिए

ढखेरवा की पीएनबी बैंक का मामला, मैनेजर सस्पेंड

अवध की आवाज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी ,निघासन। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बैंक शाखाओं में बिचौलियों के द्वारा किस तरह से काली कमाई का खेल खेला जा रहा है। जिसका जीता जागता उदाहरण ढखेरवा की पीएनबी बैंक की शाखा मात्र काफी है। यहां बैंक कर्मियों की मिलीभगत से बिचौलियों के द्वारा मुद्रा लोन के नाम पर करीब चार करोड़ की हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है। मामला चर्चा में आने के बाद शाखा के उच्च अधिकारियों ने निवर्तमान मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है। ढखेरवा लखाही में संचालित पीएनबी बैंक की शाखा में कुछ स्थानीय बिचौलियों ने दर्जनों ग्रामीणों के नाम पर मुद्रा लोन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके खातों से करीब चार करोड़ रुपयों की बड़ी रकम डकार गए हैं। काफी दिलचस्प की बात तो यह है कि विभिन्न ग्रामीणों के खातों से इतनी बड़ी रकम निकल गई और उन्हें भनक तक नहीं लगी। सूत्रों की माने तो यह रकम बीते वर्ष जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 तक चार माह के मध्य निकाली गई है। मामला चर्चा में आने के बाद जब बैंक के उच्च अधिकारियों की टीम ने शाखा में औचक निरीक्षण कर मुद्रा लोन की हकीकत परखी और रिकवरी के लिए संबंधित खाताधारकों से संपर्क किया तब उनके होश उड़ गए। और पूंछतांछ के दौरान खाताधारकों ने बताया कि वह बैंक से किसी प्रकार का कोई लोन नहीं लिया है। बिचौलियों के द्वारा ठगी का शिकार हुए खाताधारकों ने कस्बा रकेहटी निवासी एक भाजपा नेता, गांव चचरा निवासी एक सपा कार्यकर्ता और बैरिया निवासी एक मंदिर के बहुचर्चित बाबा समेत कई अन्य लोगों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ ही एसडीएम निघासन एवं कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है।

इन ग्रामीणों के खातों से निकाली गई रकम

संतोष कुमार पुत्र मनोहर लाल 9, 90 लाख, रमेश कुमार पुत्र भकासू 9, 90 लाख निवासी कठरियन पुरवा तोताराम पुत्र रामकुमार 5, 50 लाख, मिट्ठू पुत्र हरिद्वारी 5, 50 लाख,कमलेश पुत्र सीताराम 3, 50 लाख निवासी गण चचरा तथा इसी तरह से विभिन्न गांवों के दो दर्जन ग्रामीणों के खातों से करीब चार करोड़ की रकम निकाली गई है। शाखा प्रबंधक अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही इस फर्जीवाड़े में शामिल दूसरे लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। पवन कुमार क्षेत्रीय प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक।

राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस पर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

फाईलेरिया से पीड़ित रानी को मिला नेटवर्क का सहयोग

अवध की आवाज ब्यूरो

लखनऊ। पिछले करीब 25 सालों से मुझे पैरों में सूजन है। कभी कभी तेज बुखार आता है, सूजन बढ़ भी जाती है, बहुत झाड़ फूंक कराया, तेल मालिश सब करके देखा, लेकिन आराम जैसा आराम नहीं मिलाद्य गाँव के बाकि लोगों को देखकर डर लगता है कि कहीं किसी दिन हमारा हाल भी ऐसा न हो जाये। मुझे पता चला कि आज गाँव में कुछ लोगों को बहुत आराम हुआ तो हम भी यही जानने के लिये बैठक में आये हैं। यह कहना है बक्शी का तालाब ब्लॉक के मदारीपुर गाँव की रानी का।

रानी ने अपनी आप बीती मदारीपुर गाँव में राष्ट्रीय फाईलेरिया दिवस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बतायीद्य श्री गुरुकृपा फाईलेरिया उन्मूलन समिति के सदस्यों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी ने अपने अनुभवों को साझा किया, और आने वाले समय में होने वाले सामूहिक दवा सेवन (एमडीए) अभियान में सभी को दवा खाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। समिति के अध्यक्ष जमुना प्रसाद जी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वह भी पिछले 40 वर्षों से इस रोग के साथ जी रहे है।

उन्होंने बताया कि उन्हें अंडकोष में फाईलेरिया थाद्य ऑपरेशन के बाद स्थिति में सुधार है, लेकिन वह बीता समय कभी नहीं भूल सकते, जब इस रोग के कारण 3–4 दिन तेज बुखार और दर्द में पड़े रहते थे, एक तरह से उन्होंने अपनी पूरी जवानी इस रोग का दर्द झेलने में गुजर दीद्य इस समिति के माध्यम से सभी को यह सन्देश देना चाहते है कि एमडीए राउंड में आशा और आँगनवाड़ी के द्वारा खिलाई जाने वाली फाईलेरिया से बचाव की दवा सभी को जरूर खानी चाहिए।

फाईलेरिया से पीड़ित रानी ने पहली बार इस समिति की बैठक में प्रतिभाग किया है, समिति ककी सदस्य मनोरमा के द्वारा उन्हें बताया गया, कि वह झाड़ फूंक के चक्कर में न रहे, स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसकी दवाई ले, और नियमित रूप से व्यायाम करे और प्रभावित अंग की सफ़ाई रखे। मनोरमा बताती हैं कि अक्सर लोग फाईलेरिया के इलाज में घरेलु नुक्से अपनाते है या भ्रांतियों में ही फसकर रह जाते है, जबकि समय से इसके इलाज और निर्धारित पैमानों पर देख रेख की जाये तो फाईलेरिया से पीड़ित मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। लापरवाही बरतने पर स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। सेंटर फॉर एडवोकेसी से जनपद के समन्वयक सर्वेश पाण्डेय ने बताया कि गाँव में फाइलेरिया रोगियों का नेटवर्क बनाया गया है, जिससे जुड़ने के बाद सभी मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्शी का तालाब में पंजीकरण कराकर चिकित्सक के माध्यम से दवा दिलाई जाती है। मरीजों को रुग्णता प्रबंधन और दिव्यांगता निवारण (एमएमडीपी) का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वह सही तरीके से व्यायाम और प्रभावित अंगों की साफ सफ़ाई रखकर रोग को बढ़ने से रोक सके। कार्यक्रम में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च से राज्य स्तरीय समन्वयक सोनम राठौर, ब्लॉक समन्वयक अखिलेश, समिति के सदस्य कन्हई, रामधार, विद्यावती, रामकली, राजकुमारी, संजू देवी, गुड्डी देवी, रामरती, सावित्री देवी आदि मौजूद रहे।

इस बार सर्दी में रामलला खाएंगे रबड़ी, सुबह लगेगा भोग, भक्तों को भी मिलेगा प्रसाद

अयोध्या। अयोध्या। रामलला वैसे तो अभी अस्थाई गर्भगृह में हैं, लेकिन अब उनके उनके ठाठ–बाट में कोई कमी नहीं है। मौसम के अनुसार उन्हें भोग लगाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। सर्दी व गर्मी से बचाने के लिए उपकरण भी लगाए जाते हैं। हर उत्सव उनके दरबार में भव्यता से मनाया जाता है। उनके ठाठ–बाट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर रोज उनकी सुबह पंचमेवा व पेड़ा से होती है, लेकिन अबकी सर्दी से रामलला को पेड़ा के स्थान पर रबड़ी का भोग अर्पित किया जाएगा।

रामलला को सुबह से शाम तक तीन बार भोग लगता है। सुबह बाल भोग, दोपहर में राजभोग व शाम को संध्या भोग लगाया जाता है। उन्हें सुबह 6:30 बजे बाल भोग में पंचमेवा यानि की गरी, छुआरा, किशमिश, चिरौंजी व मिश्री परोसी जाती है। इसके बाद पेड़ा अर्पित किया जाता है, लेकिन अब पेड़ा की जगह पर रबड़ी का भोग लगाया जाएगा। प्रथम पाली में दर्शन खत्म होने के बाद दोपहर 12 बजे रामलला को राजभोग लगाया जाता है। राजभोग में उन्हें दाल, चावल, रोटी–सब्जी अर्पित की जाती है। आखिरी भोग संध्या भोग होता है जो दूसरी पाली में दर्शन खत्म होने के बाद शाम 7:30 बजे लगाया जाता है। संध्या भोग में पूड़ी, सब्जी और खीर अर्पित की जाती है।

श्रीराम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि अब रामलला के ठाठ–बाट में कोई कमी नहीं है। रामलला को खीर बहुत पसंद है। जिसे पंचमेवा व मखाना से बनाया जाता है। हर रोज एक बार उन्हें खीर जरूर परोसी जाती है। मुख्य अर्चक ने बताया कि रामलला का भोग शुद्ध देशी घी में तैयार किया जाता है। इस बार सर्दी में उन्हें रबड़ी का भोग लगाने की तैयारी है। इसको लेकर ट्रस्ट की सहमति मिल गई है। सुबह बाल भोग में उन्हें रबड़ी भी अर्पित की जाएगी। इस दौरान मंदिर में मौजूद भक्तों को प्रसाद भी दिया जाएगा।

रामलला भले ही बालरूप में विराजमान हों बावजूद इसके वह हर एकादशी को व्रत रहते हैं। उन्हें फलाहार का भोग लगाया जाता है। इसमें कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, पकौड़ी व सेंधा नमक से बनी सब्जी परोसी जाती है। रामलला के भोग में लहसुन–प्याज निषिद्ध होता है। उन्हें मसूर की दाल भी नहीं अर्पित की जाती, अन्य दालें उन्हें पसंद हैं। रामलला की प्रतिदिन पांच बार आरती होती है।

आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि रामलला की सुबह सात बजे शृंगार आरती, दोपहर 12 बजे भोग आरती व शाम को दर्शन बंद होने के बाद करीब 7:30 बजे संध्या आरती होती है। ट्रस्ट ने शृंगार व भोग आरती में जहां 30–30 भक्तों को शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं संध्या आरती में 60 भक्त शामिल हो सकते हैं। इसके लिए ट्रस्ट पास जारी करता है।

फैसला: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में लगाने पर रोक, कोर्ट ने टिप्पणी संग जारी किया आदेश

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत अन्य दूसरे कामों में लगाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजा है जिससे कि वह संबंधित जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर सकें। मालूम हो कि प्रदेश में 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला मनीषा कनौजिया व एक अन्य की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि वे बाराबंकी जिले के आंगनबाड़ी केंद्र सिटी गुलेरिया गरदा में बतौर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें प्रशासन ने स्थानीय निकाय चुनाव में बतौर बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) की ड्यूटी में लगाया है। यह केंद्र और राज्य सरकार की आदेशों व निर्देशों में खिलाफ है। इस तैनाती से क्षेत्र में बच्चों व माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था प्रभावित होगी। याचियों का तर्क था कि चुनाव के काम में अन्य ग्राम स्तर के कर्मियों को लगाया जा सकता है। उधर, डीएम व अन्य पक्षकारों की ओर से जवाब में कहा गया कि चुनाव का कार्य सर्वोच्च अहमियत वाला है। ऐसे में सभी अफसरों को इसमें सहयोग करना होता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं का काम काफी अहमियत वाला होता है। इनकी चुनाव या किसी अन्य काम में ड्यूटी से धात्री, गर्भवती समेत अन्य के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया।

फतेहपुर डिपो की बस और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर, एक यात्री की मौत, 22 घायल

रायबरेली। रायबरेली के बछरावां कोतवाली क्षेत्र स्थित बांदा–बहराइच राजमार्ग पर नंदा खेड़ा गांव के पास रोडवेज बस व

ट्रैक्टर ट्राली की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बस यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। इसमें से गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य के बछरावां और फिर वहां से जिला अस्पताल के लिए भेजा गया है।

लखनऊ से मुसाफिरों को लेकर फतेहपुर डिपो की बस फतेहपुर जा रही थी। शुक्रवार की रात लगभग 9रू00 बजे नंदा खेड़ा गांव के पास रोडवेज बस की ट्रैक्टर ट्राली से भिड़ंत हो गई। हादसे में रोडवेज बस पर सवार अनुराग (28) पुत्र सोहनलाल, सचिन (22) पुत्र उमेशचंद्र, अजय कुमार (32) पुत्र सुरेंद निवासी खागा फतेहपुर, धर्मेंद्र (35) पुत्र राम सुंदर निवासी लालगंज लोनी, विमल कुमार (58) पुत्र सोमनाथ मिश्रा निवासी दयालुपुर लालगंज, आरके सिंह (58) पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी सूदन खेड़ा लालगंज, अल्पेश गौतम (29) पुत्र विजय प्रकाश निवासी फतेहपुर, सुरेंद्र कुमार (60) पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी फतेहपुर, सचिन कुमार (22) पुत्र विनय कुमार फतेहपुर, रजनीश (21) पुत्र मिथिलेश ऐहर लालगंज सहित अन्य 22 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया है। घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। अजय कुमार, विनोद कुमार, अल्पेश गौतम, सुरेंद्र कुमार की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे में उज्जवल मौर्य पुत्र सुरेश मौर्य (20 वर्ष) सिविल लाइन फतेहपुर की मृत्यु हो गई है।

थानाध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि मामले की सूचना मिलने पर पुलिस घायलों को लेकर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंची, जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बस खचाखच भरी हुई थी और ट्रैक्टर ट्राली में ही ईटें लदी थीं। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। बस के चालक और परिचालक भी मौके पर नहीं मिले। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है।

पूर्व विधायक विजय मिश्र की प्रयागराज में 10.65 करोड़ की संपत्ति जब्त, करीबियों पर भी कसा शिकंजा

भदोही। समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को प्रयागराज में उनके परजिनों की 10 करोड़ 65 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर दी गई। भदोही पुलिस और प्रयागराज के मेजा तहसील की

राजस्व टीम ने चांद खमरिया पहुंच कर यह कार्रवाई की।

बाहुबली पूर्व विधायक और गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत अवैध तरीके से अर्जित की गई सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। आरोप है कि पूर्व विधायक ने अपनी भाभी दुर्गेश देवी सहित भतीजे सतीश मिश्रा, आशीष मिश्रा, राहुल मिश्रा और अमित मिश्रा के नाम पर मौजा चांद खमरियां तहसील मेजा जनपद प्रयागराज में दो जगहों पर 23 बीघा से अधिक भूमि अपने प्रभाव का अनुचित प्रयोग करते हुए वास्तवित मूल्य से कम दाम पर रजिस्ट्री कराई थी। इस संबंध में गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है। लगभग दो हफ्ते पहले जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने उक्त भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को मेजा तहसील की राजस्व टीम की मौजूदगी में प्रयागराज पहुंची भदोही पुलिस ने जब्तीकरण की कार्रवाई की। कुर्क की गई जमीन की वास्तवित कीमत 10 करोड़ 65 लाख 75 हजार रुपये है।

थाना समाधान दिवस पर एसएसपी ने सुनी जनता की फरियाद

अयोध्या। जनपद अयोध्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,अयोध्या प्रशांत वर्मा व क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना कोतवाली कैण्ट पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गम्भीरता से लेकर शत–प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद

के सभी पुलिस कर्मियो को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करें, जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके।

प्रदेश सरकार की निशुल्क स्वाथ्य व्यवस्था जिला महिला अस्पताल के गेट पर दम तोड़ रही है,अल्ट्रा साउंड में लगा ताला

अवध की आवाज ब्यूरो

गोण्डा। उ0प्र0 सरकार के निशुल्क दवा और इलाज का देवी पाटन मंडल मुख्यालय के महिला अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ रही है,सरकार के सारे दावे यहां खोखले साबित हो रहे है पिछले एक वर्ष से यहां का अल्ट्रा साउंड सफेद हाथी बना हुआ है अस्पताल में दिखाने वाली व भर्ती मरीजों को अस्पताल के बाहर प्रायवेट अल्ट्रा साउंड से मोटी रकम देकर अल्ट्रा साउंड कराना पड़ रहा है। ये देवीपाटन मंडल मुख्यालय का एक मात्र जिला महिला अस्पताल है जहां प्रति दिन साढ़े तीन सौ से लेकर चार सौ महिला मरीजो की ओपीडी में देखा जाता है और प्रति दिन 40 से 60 डिलेवरी होती

है। इन मरीजो के लिये अस्पताल में लाखों रुपये की लागत से अल्ट्रा साउंड की मशीन लगी हुई है लेकिन अस्पताल अल्ट्रा साउंड का डाक्टर न होने के कारण पिछले एक वर्ष से उधार के डाक्टर से हफ्ते में दो तीन दिन अल्ट्रा साउंड होता था लेकिन पिछले 4 माह से अल्ट्रा साउंड में ताला लगा हुआ है जिसके कारण महिलाओं को छे सौ से लेकर सात सौ रुपये बाहर से अल्ट्रा साउंड कराना पड़ता है। इस सम्बंध में अस्पताल की सीएमएस सुषमा सिंह का कहना है की चार माह पूर्व यहां डाक्टर ए के राय उनका ट्रांसफर हो जाने के कारण चार माह से अल्ट्रा साउंड बन्द है मैने कई बार शासन को भी लिखा लेकिन डाक्टर की तैनाती नही हुई जिसके कारण बाहर से अल्ट्रा साउंड कराना पड़ता है।

योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा, अस्पताल आने वाले हर मरीज को मिले बेड

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डेंगू और कोविड को लेकर अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल बने। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस जरूरी है। घर–घर जाकर स्क्रीनिंग कराएं जिससे संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले साथ ही उसकी विधिवत चिकित्सकीय जांच हो। उन्होंने कहा कि डेंगू व अन्य संचारी रोगों की प्रदेशव्यापी समीक्षा की जाए।

उन्होंने कहा कि डेंगू व कोविड की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाएं। सीएम ने कहा कि डेंगू टेस्टिंग और प्लेटलेट्स की जांच की सुविधा को बेहतर की जाए। उन्होंने अधिकारियों के बैठक में कहा कि धान खरीद की समीक्षा की जाए। हर जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण फसल के नुकसान की समीक्षा की जाए। उसके साथ ही उन्हें सरकार से मिलने वाली धन राशि को तत्काल मुहैया कराई जाए। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले को सुचारु रुप से आयोजन के लिए विशेष सचिव, माघ मेला एवं एसपी माघ मेले की तत्काल तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। मेलों पर्वों व त्योहारों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

ग्राहकों को नहीं मिल रहा न्याय, आत्मदाह की चेतावनी

ढखेरवा की पीएनबी बैंक से मुद्रा लोन के नाम पर चार करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

अवध की आवाज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। ढखेरवा चौराहे की पीएनबी बैंक शाखा से मुद्रा लोन के नाम पर बिचौलियों के द्वारा ठगी का शिकार हुए खाताधारकों को किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस चौकी से कोतवाली तक चक्कर काट कर थक चुके खाताधारकों को न्याय ना मिलने से वह आत्मदाह की चेतावनी दे दी है। ज्ञात हो कि ढखेरवा लखाही की पीएनबी बैंक शाखा से कुछ बिचौलियों के द्वारा दो दर्जन ग्रामीणों के बैंक अकाउंट से मुद्रा लोन के नाम पर करीब चार करोड़ रुपयों की हेराफेरी की है। मामला चर्चा में आने के बाद शाखा के उच्च अधिकारी क्षेत्र में रिकवरी के लिए जहां डेरा डाले हुए हैं तो वहीं बिचौलियों के द्वारा ठगी का शिकार हुए सभी खाताधारक न्याय पाने के लिए दर–दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी पुलिस प्रशासन से उन्हें किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। काफी दिलचस्प की बात तो यह है कि विभिन्न ग्रामीणों के खातों से कुछ बिचौलियों के द्वारा चार करोड़ रुपयों की इतनी बड़ी रकम डकार ली गई और वह खुलेआम घूम रहे हैं। बिचौलियों के द्वारा ठगी का शिकार हुए खाताधारक संतोष कुमार, रमेश निवासी बबियारी और कमलेश, तोताराम तथा मिद्धू निवासी चचरा आदि ने कुछ बिचौलियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बताया है कि जानकारी होने पर वह पिछले एक माह से पुलिस चौकी से लेकर कोतवाली तक के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि कुछ खाताधारकों ने न्याय ना मिलने पर वह आत्मदाह की चेतावनी भी दे दी है। खाताधारकों ने इस ओर जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में पीएनबी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार ने बताया है कि फर्जी लोन के मामले में संलिप्त निवर्तमान शाखा प्रबंधक अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इस धोखाधड़ी में शामिल सभी बिचौलियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने पार्कों का किया निरीक्षण

लखनऊ। लखनऊ की मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने जनेश्वर मिश्र पार्क, डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क, लखनऊ विकास प्राधिकरण (हरिक्षेत्र) यूपी दर्शन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (उपाध्यक्ष) इंद्रमणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। सम्बंधित अधिकारी से कहा कि पार्क के अंदर जो भी केंटीन स्थापित है, उसमें ओवर रेटिंग न हो। फूड जोन के काउंटर, पार्क के बाहर भी लगाया जाए। किड्स–जोन, ओपेन जिम, बैठने की सीट की मरम्मत कराने को कहा हैं। साथ ही पार्क में लगने वाले लेजर शो के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जनेश्वर पार्क में घास कटाई छटाई, कूड़ा उठाना तीन वेंडरो द्वारा कराया जा रहा है। बैठने के बैंच सही कराये जा रहे है। मंडलायुक्त ने डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क में साफ सफाई के कार्य कराने, आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन समय से और बिना किसी कटौती के दिया जाये। वरना संबंधित वेंडर के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

यूनीव्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी के पार्टनर टेक्नोलॉजी मीट का हुआ उद्घाटन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित होटल जैमिनी कॉन्टिनेंटल में यूनीव्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी के पार्टनर टेक्नोलॉजी मीट का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपमहानिरीक्षक आईपीएस सुभाष चंद्र दुबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत वर्षों में राज्य में जो सुरक्षा का माहौल स्थापित किया है उससे प्रदेश में जनता के बीच बहुत ही सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई है। सुरक्षा टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन नए–नए तकनीक के आने से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इन सुरक्षा और सर्विलांस उपकरणों की मदद से सरकार और प्रशासन उसका पूरा लाभ जनता को पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम संचालक यूनीव्यू के ब्रांच मैनेजर योगेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह मीट हमारे पार्टनर के सुरक्षा एवं सर्विलांस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रोत्साहन को उचित सम्मान देने के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनी का अपने पार्टनरों से संबंध और मजबूत करना और उनको अपने उत्पादों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना है।

कंपनी के इंडिया के निदेशक अश्वनी कुमार ने पार्टनरों द्वारा किए गए कार्यों की खुलकर तारीफ की एवं धन्यवाद प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम प्रतिदिन कंपनी के उत्पादों में आवश्यक सुधार और नई तकनीकी को विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। अश्वनी कुमार ने आगे यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाजार है जहां अपने उत्पादों की स्थापना करने में हम सबको सहायता मिलेगी। कंपनी के मुख्य इंजीनियर सुभाष ने अपने प्रेजेंटेशन में कंपनी के उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कंपनी के अन्य कर्मचारियों जिसमें सरफराज, रूपा वर्मा ने आगंतुकों की अगवानी की एवं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी।

विद्युत विभाग से मृतक बच्चे के परिवार को दिलववाया 500000 का मुवावजा ,,संयुक्त किसान मोर्चा

अवध की आवाज ब्यूरो

सीतापुर। मिश्रिख तहसील थाना मछरेहटा अंतर्गत गढ़ी पुरवा गांव में दस नवंबर को पांच वर्षीय नाबालिग बच्चे की आकस्मिक मौत खंभे में लगी स्टे तार पर करंट उतरने के कारण खेलते समय हो गई थी!संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू को प्रकरण की जानकारी मिलने पर उन्होंने संयुक्त मोर्चा में शामिल किसान संगठन पदाधिकारियों से बात कर मुद्दे पर

आपसी सहमति के बाद घटनास्थल पर पहुंच कर परिवार की सहमति से उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया और धरना शुरू कर दिया!गांव वालों का कहना है कि यह इस तरह का तीसरा हादसा है। शाम 5रू30 बजे तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा संज्ञान न लेने पर ग्रामीणों और मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा खैराबाद चुंगी एन एच 24 पर शव रखकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया,जिलाधिकारी सीतापुर को इस प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई! इसके बाद थानाध्यक्ष मछरेहटा और नायब तहसीलदार मिश्रिख ने मौके पर पहुंचकर विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारियों से बात कर पीड़ित परिवार को पांच लाख मुआवजे की घोषणा के साथ घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज़ करवाकर कार्यवाही की बात कही!इस घोषणा के बाद संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू व वहां उपस्थित सिख संगठन जिला अध्यक्ष गुरुपाल सिंह ने मोर्चा सदस्य व किसान मंच राष्ट्रीय सचिव/ प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह से वार्ता के बाद सभी की सहमति से धरना समाप्त कर दिया।

एनटीपीसी–विंध्याचल का 41वां स्थापना दिवस समारोह भव्य आयोजन के साथ हुआ सम्पन्न

अवध की आवाज ब्यूरो

जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। एनटीपीसी–विंध्याचल परियोजना मेँ दिनांक 12 नवंबर, 2022 को एनटीपीसी–विंध्याचल के 41वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्रशासनिक–भवन परिसर मेँ आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण ई सत्य फनी कुमार ने एनटीपीसी ध्वजारोहण किया और सभी ने एनटीपीसी गीत गाया साथ ही महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण ई सत्य फनी कुमार एवं अन्य महाप्रबंधकगणों ने केक काटकर हवा मेँ गुब्बारे छोड़े और अपना हर्षोल्लास व्यक्त किया इस शुभ अवसर पर एनटीपीसी विंध्याचल के अपर महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष, उपाध्यक्षा सुहासिनी संघ श्रीमती सरोजा फनी कुमार एवं सुहासिनी संघ की पदाधिकारीगण, असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ अजित कुमार टोप्पो, यूनियन/एसोसिएशन के पदाधिकारीगण कर्मचारी एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहें अपने उद्बोधन में मुख्य महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण ई सत्य फनी कुमार ने कहा कि 12 नवंबर, 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कर–कमलों से हमारी परियोजना की नींव रखी गई थी। 01 सितंबर, 1987 को एनटीपीसी–विंध्याचल की प्रथम यूनिट 1X210 मेगावाट का कामर्शियल आपरेशन आरंभ हुआ विगत वर्षों में एनटीपीसी विंध्याचल ने उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाया है और आज एनटीपीसी ही नहीं, अपितु राष्ट्र की विशालतम विद्युत परियोजना होने के भाव से अभिभूत हैं शून्य से लेकर 4783 मेगावाट के माइल–स्टोन को प्राप्त करने के लिए विंध्याचल के कर्मठ कर्मचारियों ने विपरीत परिस्थितियों में असीम धैर्य, त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है विंध्याचल परियोजना ने प्लांट प्रदर्शन एवं विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कई बेंच–मार्क स्थापित किए हैं उन्होनें कहा कि पर्यावरण में सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए, हमने यूनिट 13 में 100 % फ्लू गैस कंडीशनिंग के लिए देश की पहली फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रणाली स्थापित की है और अन्य सभी 12 इकाइयों में FGD स्थापना का काम जोरों पर है और CPCB दिसंबर 2024 की समय सीमा से पहले पूरा कर लिया जाएगा मुख्य महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण ने कहा कि हम अपने संयंत्र में कार्बन

डाइऑक्साइड को मेथनॉल प्लांट में स्थापित कर रहे हैं, बिजली के उत्पादन के साथ–साथ पर्यावरण संतुलन का विशेष ध्यान रखते हुए, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया का पहला संयंत्र है जो प्रति दिन 20 टन CO2 अवशोषित करता है और 10 टन मेथनॉल का निर्माण करता है इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण महोदय एवं सभी महाप्रबंधकगणों ने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना करने के उदेश्य से कई पुरस्कार प्रदान किए इसी क्रम में एनटीपीसी विंध्याचल के 05 कर्मचारियों तेजबली पाण्डेय रामबचोले कुशवाहा राम गोविंद साहू रमेश प्रसाद उपाध्याय एवं शिवशरण शर्मा के 39 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वकपूर्ण होने के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही स्पेन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता Global Management challenge के विजयी प्रतिभागियों श्री सेनगुट्टुवन पीजे ए एल मोहम्मद इदरीस और श्रीमती दुर्गा संपतकुमार को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया इसके अतिरिक्त इस अवसर पर आईटी विभाग द्वारा आयोजित साइबर सिक्युर्टी जागरूकता प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभगियों को पुरस्कृत किया गया एवं सुरक्षा विभाग द्वारा कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबन्धक मानव संसाधन श्रीमती कामना शर्मा तथा धन्यवाद ज्ञापन महाप्रबंधक मानव संसाधन प्रबीर कुमार बिस्वास ने किया।

यापारी मंगल दिवस में पुराना भोपाल हाउस किराया प्रकरण का हुआ निपटारा, पुरानी दर से देगें किराया

लखनऊ। लालबाग नगर निगम में पहला व्यापारी मंगल दिवस आयोजित हुआ। जिसमें महापौर संयुक्ता भाटिया, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ,अपर नगर आयुक्त गण एवं सभी जोनल अधिकारी और टैक्स ऑफिसर मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में लखनऊ के विभिन्न बाजारों के व्यापारी भी भारी संख्या में अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पहुंचे। प्रथम व्यापारी मंगल दिवस के आयोजन पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता ने महापौर संयुक्ता भाटिया को पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। व्यापारी मंगल दिवस के अवसर पर आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने महापौर से उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पुरानी दर से भोपाल हाउस के किरायेदारों का किराया न जमा करने का विषय रखा। महापौर एवं नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को व्यापारियों का किराया तत्काल जमा करने के निर्देश दिए। व्यापारी नेता संजय गुप्ता की मौजूदगी में भोपाल हाउस के व्यापारी संचित गर्ग द्वारा व्यापारी मंगल दिवस में भुगतान का पहला चेक (26208 रू) महापौर को सौंपा। वहीं भोपाल हाउस के अन्य व्यापारी भी सोमवार को किराया जमा करेंगे। हलवासिया मार्केट के महेश सावलनी ने हलवासिया मार्केट के व्यापारियों के गलत बिल आने की समस्या रखीं। महापौर ने हलवासिया मार्केट के व्यापारियों के बिल सही किए जाने का भी निर्देश दिया। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने भूतनाथ मार्केट में पिंक टॉयलेट बनाए जाने का पत्र भी महापौर को दिया। महापौर ने भूतनाथ में पिंक टॉयलेट बनाए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल , जूते वाली गली, अमीनाबाद के पदाधिकारी सुधीर केसरवानी ने हाउस टैक्स बिल में गलत नाम चढ़ने की शिकायत की समस्या का समाधान करते हुए महापौर ने नाम संसोधन करने व्यापारी मंगल दिवस में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के साथ नगर महामंत्री राजीव शुक्ला, नगर उपाध्यक्ष मसी उज्ज जमा गांधी, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद आदिल, विवेक श्रीवास्तव, हलवासिया मार्केट के अध्यक्ष दीपक रामचंदानी महेश सावलांनी, भोपाल हाउस के संचित गर्ग, सुधीर केसरवानी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न बाजारों के व्यापारी पहुंचे।

धनगर के नाम पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाए उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ। आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एस आर दारापुरी द्वारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अलग अलग प्रेषित पत्रों में उक्त मांग उठाई गई है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को संबोधित पत्र में अंकित किया गया है कि 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अंग्रेजी में जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त शासनादेश के सम्बन्ध में पत्र में अंकित किया गया है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूचि के क्रमांक 27 पर अंकित जाति का नाम अंग्रेजी में (DHANGAR) और हिंदी में "धन्गड़" अंकित है जोकि अधिकतर सोनभद्र जिले में रहती है. इसका यह अभिप्राय है कि यह जाति धन्गड़ है न कि धनगर जैसाकि अंग्रेजी के हिज्जों से लगता है. यह ज्ञात हुआ है पच्छिमी उत्तर की पाल,गडरिया (पिछड़ी) जाति के कुछ लोग जो अपने आप को धनगर गोत्र का होने का दावा करते हैं, भी कींदहंत के नाम से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करा रहे हैं. श्री दारापुरी ने आगे कहा है कि इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए परंतु पाल,गडरिया की धनगर गोत्र वाली उपजाति के कुछ लोग अभी भी गलत ढंग से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं जिस पर तुरंत रोक लगाई जाए। अतः शासन को प्रेषित पत्र में अनुरोध किया गया है कि वर्तमान शासनादेश के अनुपालन में अंग्रेजी में कींदहंत जाति के नाम से जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि यह केवल सोनभद्र में रहने वाली धन्गड़ जाति को ही देय है न कि पालध्गडरिया (पिछड़ी जाति) की धनगर गोत्र वाली उपजाति को। पत्र में इस सम्बन्ध में उच्च प्राथमिकता पर कार्रवाही करने का अनुरोध किया गया है ताकि वर्तमान शासनादेश का लाभ अपात्र लोग न उठा सकें और धन्गड़ जाति के लोगों के अधिकारों का और अधिक हनन न हो जोकि पहले ही सरकार की गलत एवं अवैधानिक नीतियों के कारण हो चुका है। उपरोक्त के इलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित एक अन्य पत्र में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूचि के क्रमांक 27 पर अंग्रेजी में 'Dhangar' और हिंदी में 'धन्गड़' अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में आगे अंकित किया गया है कि इस क्रमांक पर हिंदी में अंकित 'धन्गड़' नाम गलत है जबकि इस जाति का सही नाम धांगर है जोकि अधिकतर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रहती है. इस बात की पुष्टि 2001 की Serie–1, Primary Census Abstract Scheduled Castes: Tables A–8 के पृष्ठ संख्या 382 की प्रतिलिपि पर उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूचि के क्रमांक 27 पर प्रविष्टी से भी की जा सकती है। इस तथा 2011 की जनगणना में इस जाति की जनगणना 'धांगर' के नाम से ही की गयी थी न कि 'धन्गड़' के नाम से। दारापुरी द्वारा प्रेषित पत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग एवं भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूचि के क्रमांक 27 पर अंग्रेजी में 'कींदहंत' और हिंदी में 'धन्गड़' अंकित नाम को संशोधित कराकर हिंदी में 'धांगर' अंकित कराने की व्यवस्था करें ताकि धाँगर जाति के लोगों को सही नाम से जाति प्रमाण पत्र मिल सकें।

व्यापारी मंगल दिवस में पुराना भोपाल हाउस किराया प्रकरण का हुआ निपटारा, पुरानी दर से देगें किराया

लखनऊ। लालबाग नगर निगम में पहला व्यापारी मंगल दिवस आयोजित हुआ। जिसमें महापौर संयुक्ता भाटिया, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ,अपर नगर आयुक्त गण एवं सभी जोनल अधिकारी और टैक्स ऑफिसर मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में लखनऊ के विभिन्न बाजारों के व्यापारी भी भारी संख्या में अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पहुंचे। प्रथम व्यापारी मंगल दिवस के आयोजन पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता ने महापौर संयुक्ता भाटिया को पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। व्यापारी मंगल दिवस के अवसर पर आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने महापौर से उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा पुरानी दर से भोपाल हाउस के किरायेदारों का किराया न जमा करने का विषय रखा। महापौर एवं नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को व्यापारियों का किराया तत्काल जमा करने के निर्देश दिए। व्यापारी नेता संजय गुप्ता की मौजूदगी में भोपाल हाउस के व्यापारी संचित गर्ग द्वारा व्यापारी मंगल दिवस में भुगतान का पहला चेक (26208 रू) महापौर को सौंपा। वहीं भोपाल हाउस के अन्य व्यापारी भी सोमवार को किराया जमा करेंगे। हलवासिया मार्केट के महेश सावलनी ने हलवासिया मार्केट के व्यापारियों के गलत बिल आने की समस्या रखीं। महापौर ने हलवासिया मार्केट के व्यापारियों के बिल सही किए जाने का भी निर्देश दिया। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने भूतनाथ मार्केट में पिंक टॉयलेट बनाए जाने का पत्र भी महापौर को दिया। महापौर ने भूतनाथ में पिंक टॉयलेट बनाए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल , जूते वाली गली, अमीनाबाद के पदाधिकारी सुधीर केसरवानी ने हाउस टैक्स बिल में गलत नाम चढ़ने की शिकायत की समस्या का समाधान करते हुए महापौर ने नाम संसोधन करने व्यापारी मंगल दिवस में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के साथ नगर महामंत्री राजीव शुक्ला, नगर उपाध्यक्ष मसी उज्ज जमा गांधी, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद आदिल, विवेक श्रीवास्तव, हलवासिया मार्केट के अध्यक्ष दीपक रामचंदानी महेश सावलांनी, भोपाल हाउस के संचित गर्ग, सुधीर केसरवानी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न बाजारों के व्यापारी पहुंचे।

छात्राओं ने पोस्टर प्रतिभाग में सड़क सुरक्षा सावधानियों का वर्णन किया

लखनऊ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली–इस आवाहन के साथ आज को नवयुग कन्या महाविद्यालय के 19 उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन एनसीसी विंग और दर्शनशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान, में लेखन प्रतियोगिता व रोड़ सेफटी क्लब व शारीरिक शारीरिक शिक्षा विभग द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार 'सड़क सुरक्षा– जीवन रक्षा' इस विषय पर 'लेखन प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय में अध्ययनरत विभिन्न विभागों की 51 छात्राओं ने लेखन प्रतियोगिता व 21 छात्राओं पोस्टर ने प्रतिभाग किया तथा सड़क सुरक्षा की आवश्यकता, सड़क पर चलते समय ध्यान में रखने वाली बातें तथा सावधानियों का विस्तृत वर्णन किया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए छात्राओं को सदैव यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com

R.N.I.- UPHIN/2012/45127

नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।